अर्थव्यवस्था को चाहिए नई कोशिशें

भारत की विकास गाथा अचानक ही अटकती दिख रही है, संसद का अगला सत्र एक ऐसा मौका है, जब इसमें नई जान फूंकी जा सकती है।

एन के सिंह
राज्यसभा सदस्य और
पूर्व केंद्रीय सचिव

चार दिन बाद संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। इस सत्र से बहुत सारी उम्मीदें हैं। कई महत्वपूर्ण विधेयक हैं, जिन्हें पास होना है। इनमें सबसे चर्चित है लोकपाल बिल। बाकी विधेयकों में कई विवादास्पद हैं और कई पर आम सहमति भी नहीं है।

भारत की विकास गाथा में अचानक ही समस्याएं दिखने लगी हैं। अभी हाल ही में मैं भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के साथ संयुक्त राष्ट्र गया था। इसके बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड सम्मेलन में मेरे भाषण भी हुए। मैंने सभी जगह पाया कि भारत की अल्पकालिक आर्थिक संभावनाओं पर शंकाएं उभरने लगी हैं। इनमें से ज्यादातर शंकाएं उन कानूनों को लेकर हैं, जिनका रास्ता रोक दिया गया है और चिंता सरकारी घाटे को लेकर भी है।

आर्थिक आंकड़ों के कारण चिंताएं बढ़ रही हैं। विश्लेषक यह मान रहे हैं कि भारत की विकास दर अब सात फीसदी से नीचे ही रहेगी। पिछले 11 महीनों में 12 बार मौद्रिक नीति की घोषणा के बावजूद मुद्रास्फीति यानी महंगाई 12.5 फीसदी के जिद्दी आंकड़ें पर डटी हुई है और इसके नीचे जाने के कोई संकेत नहीं हैं। खाद्यान्न और खाद्य वस्तुओं की कीमतें काफी ऊंची हैं। पेट्रोल की कीमतों को थोड़ा घटाया जरूर गया है, फिर भी ये काफी ऊंची हैं। अगर इन पर दी जा रही सब्सिडी को तर्कसंगत बनाया गया, तो ये कीमतें और बढ़ेंगी। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की विकास-दर 2.1 फीसदी तक पहुंच गई है और औद्योगिक उत्पादन 1.9 फीसदी तक आ गिरा है। बेरोजगारी के आंकड़े भी कमजोर बने हुए हैं। कर्ज की बढ़ी लागत और दुनिया भर के खराब माहौल के कारण निवेशकों के हौसले पस्त हैं। पूंजी की आवक कम है, और इसके कारण रुपया पिछले 32 महीनों के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। शेयर बाजार में मंदी का आलम है और उसके आसमान में उम्मीदों का टोटा है। दुनिया के आर्थिक हालात तुरंत ही सुधर जाएंगे, ऐसी भी कोई संभावना फिलहाल नहीं है। यूरो जोन के देश अपने घाटे और भारी कर्ज से जूझ रहे हैं। उनकी बैंकिंग और वित्तीय व्यवस्था शिथिल हो चुकी है। हाउसिंग मार्केट के संकट, कर्ज-संकट और भारी बेरोजगारी से ग्रस्त अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने अभी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के संकेत नहीं दिखाए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव भी सामने है और अर्थव्यवस्था में आशाएं बहुत ज्यादा नहीं हैं। इस हताशा भरे वैश्विक माहौल और घरेलू आर्थिक चिंताओं के बीच भारत की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए? संसद का अगला सत्र इसे तय करने का अवसर है।

डी. श्रीनिवास

पहली प्राथमिकता है प्रशासन को सुधारना। पिछले एक साल से सरकार कई घोटालों से मुकाबिल है, साथ ही सिविल सोसायटी का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन है। इन सबके चलते सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कदम उठाने का फैसला किया है। उसकी योजना पांच भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों को पारित कराने की है, जिनमें लोकपाल बिल, न्यायिक जवाबदेही बिल, व्हिसिल ब्लोअर्स बिल, विदेशी अधिकारियों को घूस देने से रोकने का बिल, मनी लांडरिंग बिल का संशोधन शामिल हैं। इसके अलावा सेवा पाने के नागरिक के अधिकार के बिल पर भी आम सहमति बनती दिख रही है। ये बिल अगर पास होते हैं, तो सरकार की छवि में भी सुधार होगा।

दूसरी प्राथमिकता आर्थिक विधेयकों को लेकर होनी चाहिए। कई तरह के आर्थिक विधेयक संसद से पास होने का इंतजार कर रहे हैं। इनमें से कुछ संसदीय स्थायी समितियों के हवाले हैं और कुछ कई साल से पास होने का इंतजार कर रहे हैं। इनमें बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम भी है, कंपनी विधेयक 2009 बिल भी है, प्रत्यक्ष कर विधेयक भी है, फॉरवर्ड कांट्रैक्ट नियमन संशोधन विधेयक भी है, पेंशन फंड रेग्यूलेटरी ऐंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल और बीमा कानून संशोधन विधेयक भी हैं। पेंशन बिल को भी अभी संसद में पास होना है, हालांकि कानून के बिना ही इसके लिए पेंशन रेग्यूलेटर और पेंशन फंड काम करने लग गए हैं। शीत सत्र में इन विधेयकों की किस्मत जाग सकती है।

तीसरी प्राथमिकता होनी चाहिए निवेशकों के हौसले मजबूत करने की। कई वित्तीय व दूसरे जरूरी सुधारों के मामले में सरकार ने कुछ नहीं किया है। इससे निवेश का माहौल कमजोर हुआ है और अर्थव्यवस्था को भी इसका नुकसान झेलना पड़ा है। इसके कारण निवेशक असमंजस में भी हैं। अतः तीसरी पीढ़ी के आर्थिक सुधारों की तुरंत जरूरत है। खास तौर पर न्यायपालिका, नौकरशाही, कॉरपोरेट गवर्नेंस के मामले में। साथ ही जमीन, श्रम और खनिज के बाजारों में तुरंत ही सुधार किए जाने चाहिए। ये महत्वपूर्ण सुधार फैसलों की जटिल प्रक्रिया में अलग-अलग स्तरों पर अटके पड़े हैं। इनमें मल्टी-ब्रांड रिटेल के दरवाजे खोलने से लेकर बैंकिंग क्षेत्र में निजी कंपनियों को इजाजत देने, सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने व वित्तीय सेवाओं के सुधार शामिल हैं। इनमें से कुछ को लागू करने पर विवाद है और कुछ पर सहमति का अभाव है। इनमें से कुछ ऐसे सुधार हैं, जैसे बैंकिंग, पेंशन और बीमा क्षेत्र के सुधार, जिनका निवेश दीर्घकालिक होता है और इनका इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में हो सकता है। ये निवेश हमारी कुशलता बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। चौथी प्राथमिकता है वित्तीय व्यवस्था में बदलाव की। दुनिया के आर्थिक संकट को देखने के बाद अब हमें अपनी अर्थव्यवस्था को घाटे से उबारना होगा। अभी तक भारत ऐसे कदम उठाने में नाकाम रहा है, जिनसे इस व्यवस्था को अपने पैरों पर खड़ा किया जाए। इस साल भी भारत अपने वित्तीय घाटे के लक्ष्य से बहुत दूर है। डायरेक्ट टैक्स कोड और गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स जैसे सुधार अटके पड़े हैं, इसके साथ ही सब्सिडी के खर्च को घटाने के लिए भी हमें आगे बढ़कर कदम उठाने होंगे।

इस सबको लेकर बहुत-सी चिंताएं भी हैं और उम्मीदें भी। चिंताएं इसलिए हैं कि हम कई चीजें करने में नाकाम रहे हैं और हमने अपनी विकास गाथा के लिए कई समस्याएं खड़ी कर ली हैं। इसने हमारे आर्थिक और सामाजिक मसलों को जटिल बना दिया है। यह उठ खड़े होने का वक्त है। इन्हें टालने में गंभीर खतर हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)